प्रेषक,

मनीषा पंवार, सचिव एवं आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।

रोवा में

निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-1

देहराटून, दिनांक 22 जनवरी, 2010

विषयः जनजाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधिष्ठान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10. में अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 05/XXVII(1)/2010 दिनाक 05 जनवरी, 2010 एवं आपके पत्र संख्या 2886/स.क.—लेखा/अनुमांग/2008—09 दिनांक 16.11.2009 की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 में जनजाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधिष्ठान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या 31 के आयोजनेत्तर पक्ष में 41—मोजन व्यय गद में रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि निम्नित्यित शर्तों एवं प्रतियन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं—

- विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निवर्तन पर जो धनशिश रखी गयी है वह उनके द्वारा जनपद के अहरण-वितरण अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेगे।
- वित्त अनुमाम-1 के शासनादेश संख्या: 515/XXVH(1)/2009 विनोक २८ जुलाई 2009 में उत्तिक्षित समस्त शतों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- आयोजनागत / आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनस्रशियों हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया आयेगा।
- अनुदान के अंतर्गत होने वाले सन्मावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर केंशपलों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
- आय—व्यवक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से कंपल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
- यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2009-10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

- उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसी भद्र पर व्यय करने से पूर्व वितीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्रान्त करके ही किया जाए।
- 8 यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराति के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकरिमक व्यथ के संबंध में सम्पूर्ण मुख्य/लग्/तग तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया लाए और प्रत्येक बिल में टाहिनी और लाल स्थाही से अनुदान संख्या—31 तथा आयोजनेत्तर/आयोजनागत शब्द स्पष्ट शिखा जाए अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाबा होगी।
- संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं बाय की निवात से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
- यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनशशि की आवश्यकता हो तो मान का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय—सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 12 उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ सारों पर भी सुनिश्चित करें।
- बीठएम0—13 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट फल्स 2008, दिलीय नियम संग्रह राण्ड –1 (विलीय अधिकार प्रतिनिधायन नियन) विलीय नियम संग्रह खण्ड-६ भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन लनिरियह किया जाय।
- 15. यह एत्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता निवान्त आवश्यक है। अतं व्यय करतं समद मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2009—10 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या— 31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक —2225— अनुसूचित खाति जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण —02— अनुसूचित जनजातियों का कल्याण —277— शिक्षा—03— अनुतूचित जनजाति के विधालयों के लिए छात्रावास संथा एक रखाव एवं 41— मोंजन व्यय मद के नाम काला जाएगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 406(NP)/XXVII-3/2009 दिनाक १७ जनवरी,
 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीया.

(मनीषा पंतार) सचिव एवं आयुक्त ।

पृथ्वांकन संख्याः - 💯 / XVII-1/2009- 10(17)/2009 तद्दिनांक। २० ०। 🛮 । ०

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. निजी सचिव-मां) समाज कत्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- निजी सचिव-मृख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादृन।
- समस्त समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
- 10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड संविवालय परिसर, देहरादुन।
 - 12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

13. आदेश पॅजिका।

(बीरेन्द्र सिंह दताल) उप संविद्य ।